

के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संख्य-कार्य और नौबहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरमैया) :** (क) जहाजों को खरीदने के लिए पश्चिमी जर्मनी ने 1968-69 के लिए डी एम 100.78 मिलियन ऋण दिया है जिसमें डी एम 30 मिलियन अन्तःप्रशासन ऋण और डी एम 70.78 मिलियन सप्लायर का ऋण है ।

(ख) और (ग). प्रशासनिक ऋण भारत सरकार ने 25 वर्षों में जिसमें 7 वर्ष की प्रारम्भिक अनुग्रह (ग्रेस) अवधि भी शामिल है; चुकाना है और यह 3 प्रतिशत वार्षिक दर व्याज पर है । सप्लायर के ऋण के सम्बन्ध में भुगतान की औसत अवधि जहाजों की सुपुर्दगी के बाद 8 वर्ष है और वार्षिक व्याज दर 5-1/2 प्रतिशत है ।

उपरोक्त ऋण को 6 जहाज खरीदने के लिए प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है । इन में से दो जहाजों के लिए पक्के आदेश दिये गये हैं और 4 और जहाजों के लिये बार्ता चल रही है ।

राजस्थान के श्री बंश प्रदीप सिंह द्वारा गबन

9866. श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री राजस्थान के वंश प्रदीप सिंह द्वारा गबन के बारे में 20 दिसम्बर, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार ने प्रकरण पर विचार किया है और लावा के नरेश श्री वंश प्रदीप सिंह पर मुकदमा चलने की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 19क (2) के अन्तर्गत अपेक्षित स्वीकृति प्रदान की है ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तर-प्रदेश के उम्मीदवारों को अलाम

9867. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के कितने उम्मीदवार बैठे, और उन में से कितने चुने गये तथा इन में से अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का माध्यम अधिकांशतः हिन्दी होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में डूबने वाले उम्मीदवारों को नुकसान होता है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश के उन उम्मीदवारों की संख्या के सम्बन्ध में, जो 1967